



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54021

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8003 वर्ष 2026

सादिक उर्फ अटल

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: नरेंद्र कुमार, योगेंद्र पाल सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक की ओर से आज न्यायालय में प्रस्तुत पूरक हलफनामा रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. चौधरी और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. यह जमानत याचिका आरोपी-आवेदक सादिक उर्फ अटल की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 511/2025, धारा 109(1), 117(2), 132 बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन मवाना, जिला मेरठ में जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई है।

4. संक्षेप में, एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार, एफआईआर में नामजद तीन आरोपियों ने, एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर, पीड़ित को कठोर और कुंद वस्तु से चोट पहुंचाई है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपी-आवेदक ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक 12.1.2026 से जेल में बंद है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन उसका नाम जांच के दौरान धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज सूचनाकर्ता के बयान के आधार पर सामने आया। लेकिन एफआईआर या घायल के बयान में घायल को चोट पहुंचाने के संबंध में आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है और सभी आरोपियों की एक जैसी भूमिका बताई गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, घायल को घुटने का पूर्ण विस्थापन और डिस्टल वैस्कुलर चोट लगी है जो कि गैर-महत्वपूर्ण भाग पर है, लेकिन यह चोट आवेदक द्वारा नहीं पहुंचाई गई थी। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का ग्यारह मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिनका विवरण आवेदक की ओर से दायर पूरक हलफनामे के पैरा 12 में दिया गया है। यह निवेदन किया गया है कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में काफी समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत के लिए निवेदन किया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय पूर्व-परीक्षण स्तर पर नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो सकता है और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।

7. उपरोक्त उल्लिखित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के साथ-साथ इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन उसका नाम जांच के दौरान सूचनाकर्ता के बयान के आधार पर सामने आया, जो धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत बहुत देर से दर्ज किया गया था, लेकिन पीआरआई या घायल के बयान में घायल को चोट पहुंचाने के संबंध में आवेदक की कोई विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका नहीं बताई गई है, और सभी आरोपियों की सामान्य भूमिका बताई गई है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, घायल को घुटने का पूर्ण विस्थापन हुआ है, साथ ही डिस्टल वैस्कुलर चोट भी आई है जो गैर-महत्वपूर्ण हिस्से पर है, लेकिन उपरोक्त चोट आवेदक द्वारा नहीं पहुंचाई गई थी। मुकदमे के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, वह 12.1.2026 से जेल में बंद है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2024 (एससी) प्रकरण 677) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद संख्या 53, संघ भारत बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एससीसी 51** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह व्यक्तिगत मुचलका

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और दो जमानती पेश करे, प्रत्येक समान राशि का, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, या तो स्वयं या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार, अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक अवर न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) आरोपी का व्यक्तिगत बयान दर्ज करना, जिसमें वह अपने विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करे।
- (v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, अवर न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही शुरू करेगी।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन अवर न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा बांड स्वीकार किए जाने से पहले किया जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17 मार्च, 2026

आरण

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”